राष्ट्रपति के 2018 के अभिभाषण के मुख्य अंश

भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 29 जनवरी, 2018 को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने अपने अभिभाषण में सरकार की प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। अभिभाषण के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं :

अर्थव्यवस्था और वित्त

- अर्थव्यवस्था में, 2016-17 की पहली तिमाही में जीडीपी विकास में अस्थायी मंदी रही। 2017-18 की दूसरी तिमाही में इस गिरावट में बदलाव आया।
- मुद्रास्फीति, चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा कम हुआ है। 2017-18 में विदेशी मुद्रा भंडार 410 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। पिछले तीन वर्षों में एफडीआई 36 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 60 बिलियन डॉलर हो गया।
- *टैक्सेशन*: वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एंटी-प्रोफिटियरिंग अथॉरिटी का गठन किया गया ताकि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे।
- *वित्तीय समावेश*: लगभग 31 करोड़ जन धन खाते खोले गए। महिलाओं के बचत खाते का प्रतिशत 28% से बढ़कर 40% हो गया।
- *प्रधानमंत्री मुद्रा योजना* के अंतर्गत 10 करोड़ स्वीकृत ऋणों के जरिए चार लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिए गए।
- *आधार :* 400 योजनाओं का लाभ प्रदान करते हुए आधार ने 57,000 करोड़ रुपए की बचत करने में सहायता की।
- *बीमा* : *प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना* और *प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना* के अंतर्गत अब तक 18 करोड़ से अधिक गरीब जुड़ चुके हैं और दावों के रूप में उन्हें दो करोड़ रुपए से अधिक चुकाए गए हैं। *अटल पेंशन योजना* के अंतर्गत 80 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण (री-कैपिटलाइजेशन) का निर्णय लिया गया और उनमें दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया।

रक्षा और सुरक्षा

- वन रैंक वन पेंशन के अंतर्गत 20 लाख से अधिक सेवानिवृत्त पूर्व सैन्यकर्मियों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई।
- सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाली योजना को मंजूरी दी।

गवर्नेंस और कानूनी सुधार

- पिछले तीन वर्षों में 1,428 अप्रासंगिक कानूनों को रद्द किया गया।
- बार-बार होने वाले चुनावों से न केवल मानव संसाधन पर भारी दबाव पड़ता है, बल्कि विकास भी बाधित होता है। इसलिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने पर विचार किया जाना चाहिए।

कौशल विकास और रोजगार सृजन

- *अटल इनोवेशन मिशन* के अंतर्गत 2,400 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स मंजूर किए गए।
- *राष्ट्रीय उद्यमिता संवर्धन योजना* के अंतर्गत पांच लाख युवा लाभान्वित हुए।
- युवाओं के कौशल विकास हेतु दो योजनाओं: *संकल्प* और *स्ट्राइव* को मंजूर किया गया।

शिक्षा

- उच्च शैक्षणिक संस्थानों की सभी परीक्षाओं को संचालित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को स्वायत्त और स्वतंत्र संगठन के रूप में कार्य करने के लिए मंजूर किया गया।

गायत्री मान
gayatri@prsindia.org

29 जनवरी, 2018

- 20 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को स्थापित करने का लक्ष्य। इस मिशन के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के 20 चुनींदा संस्थानों को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) बिल, 2017 को संसद द्वारा पारित किया गया। बिल आईआईएम को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है।

स्वास्थ्य

- बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की गई।
- *प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों* के जरिए 800 दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई गईं। 3,000 से अधिक केंद्र स्थापित किए गए।
- डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पोस्ट ग्रैजुएट्स की 7,000 और एमबीबीएस की 13,000 से अधिक सीटें मंजूर की गईं।
- मेडिकल शिक्षा में समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा में राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन बिल पेश किया गया।
- *तीव्र मिशन इंद्रधनुष* को हाल ही में शुरू किया गया था। टीकाकरण की औसत वृद्धि दर 1% से बढ़कर 6.7% हो गई है।

सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण

- मुसलिम महिला (विवाह संरक्षण अधिकार) बिल, 2017 को लोकसभा में प्रस्तावित और पारित किया गया।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए एक बिल संसद में पेश किया गया।
- दिव्यांग जनों के लिए सरकारी नौकरियों में 4% और उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया।
- दिव्यांग जन अधिकार एक्ट, 2016 को लागू किया गया।
- पिछले तीन वर्षों में 6,000 से भी अधिक कैंप लगाकर नौ लाख दिव्यांग जनों को जरूरी और सहायक उपकरण प्रदान किए गए।

महिला और बाल विकास

- *बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ* योजना का दायरा 161 जिलों से बढ़ाकर 640 जिलों तक कर दिया गया।

श्रम

- सरकार श्रम कानूनों में सुधार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। न्यूनतम वेतन 40% से अधिक बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त श्रम कानूनों के अनुपालन के लिए रजिस्टरों की संख्या 56 से घटाकर पांच कर दी गई है।
- मातृत्व लाभ (संशोधन) एक्ट, 2017 में महिलाओं को 12 हफ्ते के स्थान पर 26 हफ्ते के अवकाश का प्रावधान किया गया है।

उद्योग और मैन्यूफैक्चरिंग

- विश्व बैंक की वार्षिक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 190 देशों में भारत की रैंकिंग 142 थी। 2017 में भारत ने अपनी स्थिति सुधारी और अब वह 100 वें स्थान पर है।
- सरकारी खरीद में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देने के लिए एक नई नीति तैयार की गई है। यह नीति घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग और सेवाओं को बढ़ावा देती है।

परिवहन और कनेक्टिविटी

- *प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना* के अंतर्गत 2019 तक प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 2014 में 56% की तुलना में अब तक 82% से अधिक गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है।
- *सागरमाला* कार्यक्रम के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, स्मार्ट पोर्ट इंडस्ट्रीज सिटीज़ और दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट में विशेष आर्थिक जोन्स पर काम शुरू हो चुका है।
- *भारतनेट* प्रॉजेक्ट के अंतर्गत एक लाख से अधिक पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल (ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी) से जोड़ा जा चुका है।
- मेट्रो रेल नीति तैयार की गई थी, जिसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया था।

वर्तमान में 11 शहरों में मेट्रो का कार्य प्रगति पर है।

- *भारतमाला* को मंजूरी दे दी गई है और 5.3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रॉजेक्ट के अंतर्गत लगभग 53,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाइवे) को चिन्हित किया गया है।
- *उड़ान* के अंतर्गत 15 महीनों में 56 एयरपोर्ट्स और 31 हेलीपैड्स को कनेक्ट करने के लिए काम शुरू हो गया है। अब तक ऐसे 16 एयरपोर्ट्स से उड़ानें शुरू हो चुकी हैं।

बिजली

- भारत बिजली का नेट एक्सपोर्टर बन गया है। सरकार ने एक राष्ट्र एक ग्रिड पर काम पूरा करके राज्यों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है।
- करीब 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई गई है।
- *प्रधानमंत्री उज्जवला योजना* के अंतर्गत 3.3 करोड़ से अधिक के गैस कनेक्शन दिए गए हैं।
- *उजाला* के अंतर्गत 28 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब बांटे गए हैं और निजी क्षेत्र ने 50 करोड़ एलईडी बल्ब बेचे हैं। इससे सालाना 40,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

शहरी और ग्रामीण विकास

- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 93 लाख से अधिक मकान बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत ब्याज दर में 6% की राहत दी जा रही है। इसके अतिरिक्त मध्यम वर्ग के लिए दो नई योजनाओं को शुरू किया गया है।

कृषि और जल संसाधन

- कृषि उपज को नुकसान से बचाने और उसके सुरक्षित भंडारण के लिए *प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना* की शुरुआत की गई है।
- *प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना* के अंतर्गत किसानों को सस्ती और सरल बीमा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 2017 के दौरान 5.7 करोड़ किसानों को संरक्षण प्रदान किया गया।
- डेयरी क्षेत्र में एक नई योजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत 11,000 करोड़ रुपए का 'डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड' बनाया गया है।
- सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के प्रति प्रतिबद्ध है। अब तक 36,000 करोड़ रुपए की कृषि पैदावार का ई-नाम पोर्टल पर व्यापार किया जा चुका है।
- भारतीय वन (संशोधन) बिल, 2017 को संसद द्वारा पारित किया गया। बिल बांस शब्द को हटाने के लिए वृक्ष की परिभाषा में संशोधन करता है।

विज्ञान और तकनीक

- इसरो ने एक साथ 104 सेटेलाइट लॉन्च किए। जून 2017 में भारत के जीएसएलवी एमके III की पहली डेवलपमेंटल फ्लाइट सफल रही।
- मई 2017 में इसरो ने दक्षिण एशियाई सेटेलाइट को लॉन्च किया। इसके अतिरिक्त 12 जनवरी, 2018 को इसरो ने पीएसएलवी-सी40 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसी के साथ देश ने अंतरिक्ष में सेटेलाइट्स की सेंचुरी लगाई।

उत्तर पूर्व का विकास

- 100% केंद्रीय सहायता वाली उत्तर पूर्व विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना के अंतर्गत पेय जल आपूर्ति, ऊर्जा और शिक्षा से संबंधित प्रॉजेक्ट्स को पूरा किया जाएगा।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।